centres as well as for small hospitals but not for bigger ones which are not situated in the rural areas.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Only construction of buildings for the hospitals will not do. The running of hospitals by the Government in the rural ^reas is very unsatisfactory. So, construction of buildings only will not do. The running of hospitals will also be required. When you spend money on the construction of hospitals if they are not being run, it win be of no use.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I will only say one thing. Under this programme it was not evisaged. There are schemes under which certain hos_. pitals constructed and run by public institutions are being helped by the State Governments and also partially by the Central Government, in both capital expenditure and revenue expenditure. They come under the Health Ministry and not under the Rural Development Ministry.

*162. *[The Questioners (Shri Dig vijay Singh and Shri Satya Prakash Malaviya) were absent^ For answer* vide col................ infra.]

*163. *[The Questioners (Shri Sikan_ der Bakht and Shri Viren* J. *Shah) were absent. For answer* vide col................ infra.]

Modernisation of Public Sector Fertilizer Unit

*164 SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for modernisation and expansion of the Public Sector Fertilizer units, if so, the details thereof, unit-wise and by when it is likely to be implemented;

(b) what is the working condition of the plant of Paradeep Phosphate Ltd.. after the withdrawal of investment from the joint venture by Nauru Gov's ernment; and

(c) the details of the quantity Of DAP produced by this plant against the targetted production during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House,

Statement

(a) The details of some of the major modernisation/expansion schemes of the public sector fertilizer units are given in the Annexure. *[See* Appendix 171, Annexure No. 26]

(b) The overall performance of the company, including production performance of its Paradeep based plants, is expected to improve with the capital restructuring agreed to by the Government recently.

(c) The quantities of DAP produced by Paradeep Phosphates Limited (PPL) vis-a-vis its targets during the last three years given below:

Year	Production of DAP (in lakh tonnes) Target	Actual production
1991-92	7.20	6.41
1992-93	7.25	5.23
1993-94	4.00	3.85

श्री वीरेन्द्र कटारिया : चेयरमैन साहब, वजीर साहब का जो स्टेटमेंट सभा के पटल पर रखा है, उसको देखते हुये मैं पूछना चाहता हूं कि और पूछने से पहले कहना चाहता हूं कि हमारे देश में किमियाबी खाद की बहुत कमी है। हमारा फारेन एक्सचेंज, कीमती फारेन

एक्सचेंज खाद को बरामद करने में खर्च होता है। हमारे देश में खाद की प्रोडक्शन के लिये बहुत काम हुआ है और बड़े बड़े ज्वायंट कारखाने लगाये गये हैं ।

MR. CHAIRMAN: Please put the question. Please frame the question. The Minister himself has admitted it in the answer.

श्री वीरेन्द्र कटारिया: सर, मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम या जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इसके अलावा वह क्या इस तजवीज पर गौर करेंगे कि खाद की कमी को दूर करने के लिये हजीरा बीजापुर–जगदीश लाइन को सिरसी तक ले जाकर और इसके अलावा नामरूप जहां गैस अवलेबल है वहां, इन दोनों जगहों पर 7:26 केपेसिटी के दो मोडर्न प्लांट लगाने की तजवीज पर वह गौर करेंगे? इसके अवाला जो उन्होंने अपने बयान में कहा है क्या वह इस तजवीज पर गौर करेंगे कि नेशनल फर्टिलाइजर के नांगल, पानीपत और भटिंडा प्लांटों को एक्सपेंड किया जाय क्योंकि पंजाब, हरियाणा का जो इलाका है वहां पर खाद की बहुत ज्यादा खपत है? और ये तीनों प्लांट भटिंडा, पानीपत और नांगल के इस इलाके में लगे हुये हैं और इनका एक्सपेंशन फार्मर्स के लिये और देश के हित में बहुत अच्छा रहेगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामलखन सिंह यादव : जहां तक फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाने का संबंध है या बन्द जो हो गई हैं हमारी फैक्टरी उनको चलाने का संबंध है हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक उनकी मरम्मत करके, रिप्लेस-मेंट करके, एक्सपेंशन करके यथासंभव जो उपाय हो सकें हम उसको बढ़ा सकें ताकि हमारे देश में खाद की कमी न हो। उसी सिलसिले में कई कदम इसमें उठाए गये हैं।

जहां तक पारादीप का सवाल है, वह फैक्टरी तो सम्भवतः, मालूम होगा सदस्य महोदय को कि इसमें नौरू सरकार का भी कुछ हिस्सा पूंजी था 49 परसेंट का, 130 करोड़ का। उन्होंने कई तरह से अनिच्छा जाहिर की इसलिये सरकार ने निश्चय किया कि उनकी पूंजी लौटा दी जाय। उसको 5 बरसों में छमाही किस्तों में पूरा लौटाने का प्रबंध किया गया है और तीन किस्तें दे दी गई हैं। खुशी की बात है कि इस सरकार ने सब सोच समझकर के कम्पनी का रिस्ट्रक्चरिंग किया। उसमें कई कदम उठाये गये हैं। भारत सरकार का भी जो हिस्सा पूंजी में बदला गया है वह 54 करोड़ 70 लाख का है। अंशदान के विरुद्ध दिया गया अग्रिम जो अंशदान में बदला गया, वह 35 करोड़ 30 लाख का है। सरकार के ऋण, जिसे प्रेफरेंस शेयर में बदला गया 117 करोड़ 65 लाख है। ऋण और बकाया ब्याज, जो माफ कर दिया, 146.39 लाख है। सूद पर जो पीनल इटरेस्ट बनाया गया था, वह 128 करोड़ 51 लाख का माफ कर दिया गया। ये सब करने से नतीजा यह हुआ कि 1993-94 में अब 47 करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया है, वरना अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसमें 80 करोड़ का सालाना हमें घाटा होता। तो इस तरह से कदम उठाये गये हैं।

जहां तक एच०एफ०सी० और एफ० सी०आई० का संबंध है, इसमें बहुत उन की हालत खराब थी। उस हालत में जो नियम है, उसके अनसार बी०आई०एफ०आर. में यह केस गया। बी०एफ०आई०आर० ने सुनवाई करके एक तो किया कि इसके बारे में दूसरी एजेंसी को मौका दिया कि तीन महीने में आप इसके बारे में स्कीम दें कि कैसे चले। साथ-साथ हमको अपना अधिकार है कि अपने विभाग से हम भी स्कीम दें कि कैसे हम इसको चला सकते हैं। उसी सिलसिले में एक और खुशी की बात है कि इस संबंध में सरकार ने एक और मंत्रियों की कमेटी बना दी है जिसके अध्यक्ष हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। उनके यहां भी हम स्कीम लेकर जा रहे हैं और हाल में, सबसे आखिर में, मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण करके उन्हें भेजा है कि आप जाकर के देखिए बरौनी में,

दुर्गापुर में और नामरूप के दोनों प्लांट में....

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, other questions will also come. Second supplementary.

श्री राम लखन सिंह यादव: वह चला रहे हैं। मैं शार्ट में कह देता हूं। उसके अनुसार हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, अगर 270 करोड़ रुपया हम तीन वर्षों में लगा देंगे तो ये चारों फैक्टरी हमारी चल जाएंगी और अच्छी तरह से चलेंगी और 8–10 वर्षों तक इन चारों फैक्टरियों में उत्पादन बढ़िया हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें मंत्री जी की जो कमेटी है, फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में, उनके पास हम जाएगे और इसको चलाने का उपाय करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कटारिया: सर, मैंने यह पूछा था कि नेशनल फर्टिलाइजर के नांगल, पानीपत और भटिंडा के प्लांट की क्या एक्सपेंशन की जाएगी और इसके अलावा नामरूप में और सिंदरी में 7:26 के दो नए प्लांट लगाने की प्रपोज़ल पर गौर किया जाएगा? मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस पर गौर किया जाएगा क्योंकि यह नेशनल इंटरेस्ट में है। इसके साथ मैं अपना दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। माननीय वज़ीर साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, 1991–92, 92–93 और 93–94 मे प्रोडक्शन आफ डी.ए.पी. इन पी. पी. एल. प्लांट एट पाराद्वीप, उसमें उन्होंने टारगेट भी दिया है और एक्च्युअल प्रोडक्शन भी दी है। 1991–92 का टारगेट 7.20 था जो 6.41 हुआ। 1992–93 में 7.25 थो जो 5.23 हुआ और 1993–94 मे 4 के बजाय 3.85 हुआ। मैं वज़ीर साहब से पूछना चाहता हूं कि एक्च्युअल उसको प्रोडक्शन केपेसिटी 10 लाख मैट्रिक टन डी.ए. पी. है।

MR. CHAIRMAN: You kindly put your question.

SHRI VIRENDRA KATARIA; My question is. Why is the full capacity not being utilised and why is DAP 1 being imported? My submission is, the price in the international market I is 215 dollars.

हम क्या उपाय करेंगे कि इन इंटरनेशनल प्राइसेज को किस तरीके से मीट करेंगे ताकि प्रोडक्शन तो 10 लाख मैट्रिक टन हो जाए, लेकिन इसमें प्रोफिटेबिलिटी भी आए। इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट का क्या सुझाव है और क्या प्रोग्राम है?

श्री राम लखन सिंह यादव: मैंने बतलाया कि गवर्नमेंट का केवल सुझाव ही नहीं है, गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है उसके अनुसार अब इस फैक्टरी से 1993–94 का जो फिगर्स आया है उसके अनुसार फाइनेंस का जो रिकंस-ट्रक्शन हुआ रिकंसट्रक्टिव मेजर्स लिया गया, उसके अनुसार अब वहां से मुनाफे में जाएगा और जो 80 करोड़ का घाटा लगता अब वह 47 करोड़ के मुनाफे में जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें नोरू सरकार की जो पूंजी थी 49 फीसदी, इसमें उन्होंने ढिलाई दिखलाई अंत में उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं लेंगे, इससे हट जाएंगे। तो इस तरह से कई लीगल बखेड़े भी आए। अब तय हो गया है कि उनकी जो पूंजी थी हम लौटादें। इसे सरकार ने मान लिया है। वह मैंने कहा कि दस किश्तों में 5 वर्षों में एक-एक करके वहां दे दिया जाएगा। अब तीन किश्तें वे भी दी गई हैं। कई तरह के जो मेजर्स लिए गए हैं इसको मुनाफे में लाने के लिए ताकि पूरा हो। उसके लिए मैंने पहले अपने उत्तर में बतला दिया है। इसलिए इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो कदम उठाया गया है वह सही है और इसको देखकर के फिर आगे की कार्रवाई की जो आवश्यकता पड़ेगी, समझबूझ करके वह सब देखा जाएगा।

श्री रामजीलाल : धन्यवाद सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने विस्तारपूर्वक अपने उत्तर में बताया है और सप्लीमेंट्री में भी बताया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इससे देश में सभी फर्टिलाइजर डी०एस०यू० के एस०के०यू० के मौडनाइज करने से देश में फर्टिलाईजर की कमी दूर हो जाएगी? यदि हरियाणा के एन० एफ०एल० पानीपत प्लांट तथा दूसरे फर्टिलाइजर प्लांट में कितनी-कितनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? इस तरह डी०ए०पी० की कमी के कारण विदेशों से करोड़ों रुपए की खाद मंगानी पड़ती है। तो यह कब तक पूरा हो जाएगा? क्या कोई नया प्लांट लगाने का सरकार का इरादा है?

श्री राम लखन सिंह यादव : देश में फर्टिलाईजर की कमी नहीं रहे या अधिक से अधिक हम उसकी पूर्ति कर सकें, तो सभी दिशाओं में सरकार की नजर है। कुछ तो एक्सपेंशन करने का विचार है और कर भी रहे हैं, कुछ उसमें रिप्लेसमेंट करने का है, उसका भी उपाय हो रहा है। सरकार के अलावा प्राईवेट सेक्टर में जो लोग नई फैक्टरी बना सकते हैं उससे भी हमारे देश में फर्टिलाईजर का उत्पादन बढ़ेगा और उसके बाद इसके अलावा भी दो-तीन वर्षों में आगे तक की जो स्कीम हमारी है, उसके अनुसार मैं समझता हूं कि किसानों का रोज डिमांड बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी पूर्ति करने में हम बहुत दूर तक सक्षम हो गए हैं। मैं माननीय प्रश्नकर्ता को बतला दूं, इस साल का 1994-95 का जो हमारा प्रोडक्शन प्लान है, उसको सब मिलाकर के 10 फीसदी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बढ़ने की उम्मीद है और निश्चित समय में बढ़ जाएगा। इसलिए हर साल बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जैसा आपको याद होगा प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है। तो सब करने के बाद किसानों को और भी आवश्यकता पड़ेगी तथा उसके लिए भी जहां से होगा हम उसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए किसानों को इस देश में खाद की कोई कमी नहीं होगी। जो डिमांड होगी उसके मुताबिक हम उसे पूरा करने का प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, हमारे सार्वजनिक उपक्रम के रासायनिक खाद के कारखानों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं होने के कारण ही आज हम विदेशों से रासायनिक खाद आयात कर रहे हैं और यह हम जो अपने देश में खाद बना रहे हैं, उससे साबित हो रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नई तकनीकों की खोज की जाए। मैं इस सन्दर्भ में आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक तकनीक है कोयले से रासायनिक खाद बनाने की। चीन में इस तकनीक के आधार पर कारखाने चल रहे हैं। हमारे पास कोयले के विपुल भण्डार हैं। आदरणीया श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोयले पर आधारित एक रासायनिक खाद के कारखाने का कोरबा में, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में वह स्थान स्थित है, वहां शिलान्यास भी किया था, वह योजना अब ठंडे बक्से में डाल दी गई है। अब जबकि नई तकनीक चीन ने बना ली है और कोयले से रासायनिक खाद बन सकती है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसका नए सिरे से परीक्षण कराया जाएगा? और हमारे पास जो कोयले के विपुल भण्डार हैं, उन का प्रयोग करके हम रासायनिक खाद बड़ी मात्रा में बनाएंगे? क्या कोरबा के कारखाने में जिसमें कई करोड़ रुपए पहले भी व्यय हो चुके हैं, इस व्यय को बढ़ा कर उस कारखाने में रासायनिक खाद बनाई जाएगी?

श्री राम लखन सिंह यादव : पहली बात तो यह है कि कोयले के जरिए अगर हम अपने यहां खाद की पैदावार बढ़ा सकें, नई फैक्टरी में काम कर सकते हैं, यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमको विचार करना चाहिए लेकिन अभी इन्होंने कहा कि ठंडे बक्से में रख दिया गया है तो माननीय सदस्य के

प्रयास से मैं चाहूंगा कि उसको ठंडे बक्से से निकाल कर गर्म बक्से में लाया जाए और उसके संबंध में इनके जो तजुर्बे हैं, इनको जो जानकारी है, इनके साथ बातचीत करके उनसे हम फायदा उठाएंगे। अगर ऐसी कोई तकनीक निकल सके कि कोयले से हम खाद बना सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMAHA RAO); Sir, coal based fertilizer factories were opened in the early seventies at two places— one in Ramaundam and the other in Talcher. After a lot of experience they came to the conclusion that this technology itself was becoming wasteful and it could not be really procee. ded with. For the first time, I learnt that in China the same technology or a similar technology of manufacturing fertilizer from coal had successfully been going on_ We will certainly go into it. But I know personally that so far it has not been possible to make it economical and make it successful. Theoretically, yes, it is possible and we wanted "to do it because as we know coal deposits are enormous in our country and we could have done it. But the technology does not seem to have succeeded so far. But if thert is any new breakthrough, we will certainly go into it_

SHRI S. S. SURJEWALA: Mr. Chairman, Sir, in reply to part (c) of the question regarding production of phosphate in the Paradeep plant, the Minister has stated that the targets were gradually falling from 7.20 lakh tonnes in, 1991-1992 to 4.00 lakh tonnes in 1993-94. Similarly, the targets fixed also could not be achieved. I would like to ask some specific questions. What are the grounds for fixing low targets and what is the reason for not achieving the targets? This is one question. I would like to point out that there is a shortage of fertilizer in our country. Two days ago_ there was a story published in the front page of *Midday,* a Delhi-based evening paper in which it was stated that there was a nexus between the traders and the top-level people of the NFL. Some people from Haryana posted in the field areas, Yamuna Nagar and Kurukshetra, were also said to be involved. A case by the CBI has been registered amounting to a very huge amount... *(interruptions)...*

So, I would also like to know from the Minister whether this fact is in his knowledge and whether he would try to save the farmers 'from the clutches of the unscrupulous officers and traders.

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक उसमें फर्टीलाइजर की कमी होने के कारण हैं तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में ही दे दिया है कि सारे देश से जो हमारा एग्रीमेण्ट था, उसके चलते मेन कारण हुआ और इसके साथ और भी कई कारण हो सकते हैं जिसको देख करके हमने कदम उठा लिया है। उसका भी मैंने विस्तृत ब्यौरा पहले दे दिया है। जहां तक केस की बात है मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं जब तक मैं उसको देख न लूं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, इस समय मैं इनकी इनफार्मेशन को ग्रहण कर लेता हूं और इस संबंध में मैं पता लगाऊंगा की क्या सच्चाई है।

*165. [The *Questioners* (Dri *Murli Manohar Joshi and Shri Trilokinath Chaturvedi) were* absent. *For answer vide* col................ tnfra.]

Decontrol of fertilizers

*166. SHRI K. M. KHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to decontrol some varieties of fertilizers very soon;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this step will help the farmers in any way;